

प्रेषक,

डॉ रणवीर सिंह,  
संवित,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिला सहायक निबन्धक,  
सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुदान:-1देहरादूनदिनांक २० सितम्बर, 2007

**विषय:-** चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये सहकारिता विभाग की आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जाति उपयोजना (जिला सेक्टर) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति। महीदय

इ उपर्युक्त विषयक अपर निवापक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड के पत्र रख्या 1953/ नियो०/गि०यो०/एस०सी०वी०/ 2007-08 दिनांक 24.8.2007 पो रान्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 में सहकारिता विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की अनुसूचित जाति उपयोजना (जिला सेक्टर) में कुल रुपया 24.73 लाख रुपये (रु० चौबीस लाख तिहात छार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार निम्नाकिञ्च शर्तों के अधीन व्यय करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) समाज कल्याण नियोजन प्रवर्गेष्ट द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट <http://gov.ua.nic.in/socialwelfarempr>, पर अनुसूचित जाति उपयोजना की मासिक प्रगति, योजनावार लाभान्वित लाभार्थियों की सूची तथा सामूहिक लाभ वाले कार्यकर्ता की सूची जनपदवार उपलब्ध करायें।

(2) राज्य गठन के उपरान्त दर्खार माह मार्च की अनुसूचित जाति उपयोजना की प्रगति एवं योजनावार लाभान्वित लाभार्थियों की सूची/सामूहिक योजनाओं का दर्खार /जनपदवार पूर्व विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय।

(4) रानी नारीकर्मों वी कार्यक्रम/नारीक लक्ष्यों का निर्धारण तत्काल किया जाय एवं परीक्ष रतार पर भी निर्धारित विधि गये लक्ष्यों वी रूपना उपलब्ध करा वी जाय।

(5) उक्त धनराशि केवल अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित राहकारी समितियों के उत्थान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत परिवाय के अनुसार व्यय किया जाय तथा ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है। यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा इन्सी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी इसके

लिये रामुचित रूप से जिमेदार होगा और उनसे अनापिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह के अन्त में या अगले माह की 5 तारीख तक दी०एम०-१३ पर नियमित रूप से वित्त विभाग/ शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करे।

(7) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किरी ऐसे बार्थ/गद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुरितका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/संकाय अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में वित्तव्ययता निरान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मित्तव्ययता समन्वयी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुरितका गे उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(8) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय वितरण सहित शासन/ महालेखाकार, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

2. प्रश्नगत गद में गत वित्तीय वर्ष में निर्गत स्वीकृति के सापेक्ष किये गये कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं निर्धारित प्रफत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र 15 दिनों के अन्दर शासन एवं महालेखाकार उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराया जाय।

3. उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 के अनुदान संख्या -३० के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता -आयोजनागत-107-कैडिट सहकारी समितियों को सहायता 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता 800-अन्य व्यय एवं 6426-सहयोगिता के लिये वार्ज -आयोजनागत -107-जमा सहकारी समितियों को कर्ज को अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक /योजनाओं के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के ३०शा०संख्या-२०५(P)/वित्त अनुभाग-४ /२००७ दिनांक १२.९.२००७ में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोपरि।

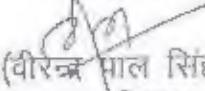
विवर  
(डॉ०रणवीर सिंह)  
संधिव।

संख्या:- ४३३ (१)/XIV-१/२००७ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1-महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी औदराय विलिंग, माजरा, उत्तराखण्ड दैहरायून ।।  
2-समस्त कोपाधिकारी / जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

- ३-निवन्धक, साहकारी समितिया, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।  
४- पिता अनुपाम-५ / रामाज मालवाण निरोजन प्रबोध, उत्तराखण्ड शारांग।  
५-निदेशक, एन०आई०सी०, राधिकालय परिसार, उत्तराखण्ड।  
६- गार्ड फाईल।

आशा रो  
  
(वीरञ्जन माल सिंह)  
अनुसन्धिव।

(2015-2016)

212